



कनाडा—भारत संबंध और खालिस्तान की राजनीति पर पुनर्विचार

कमलेश कुमारी, राजनीति शास्त्र विभाग
इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी, हरियाणा, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Author

कमलेश कुमारी

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 30/10/2023

Revised on : -----

Accepted on : 06/11/2023

Plagiarism : 05% on 30/10/2023



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

Overall Similarity: 5%

Date: Oct 30, 2023

Statistics: 173 words Plagiarized / 3333 Total words

Remarks: Low similarity detected, check with your supervisor if changes are required.



शोध सार

इस शोध लेख में भारत और कनाडा के अंतर्संबंधों के बीच जटिल रूप से वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य इस बात की व्यापक समझ प्रदान करना है कि इन कारकों ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को कैसे आकार दिया है और कैसे प्रभावित करना जारी रखा है। यह एक ऐसा अध्ययन है जो एक जटिल मुद्दे की बहुआयामी परतों के माध्यम से नेविगेट करता है, इसकी ऐतिहासिक जड़ों, इसकी समकालीन अभिव्यक्तियों और दोनों देशों के लिए इसके निहितार्थों पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है। कनाडा और भारत के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय संबंध हैं जो लोकतंत्र, बहुलवाद और मजबूत पारस्परिक संबंधों की साझा परंपराओं पर आधारित हैं। कनाडा और भारत के बीच गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध आधिकारिक संवादों, समझौतों, समझौता ज्ञापनों और कार्य समूहों के बढ़ते नेटवर्क से मजबूत हुए हैं (गुप्ता, शिव दयाल, 1990)। इस लेख में हम भारत—कनाडा संबंध, द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खालिस्तान आंदोलन वर्तमान पंजाब (भारत और पाकिस्तान दोनों) में एक अलग, संप्रभु सिख राज्य की लड़ाई है। यह मांग कई बार फिर से उठी है, सबसे प्रमुख रूप से 1970 और 1980 के दशक में हिंसक विद्रोह के दौरान जिसने पंजाब को एक दशक से अधिक समय तक पंगु बना दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार (1984) और ऑपरेशन ब्लैक थंडर (1986 और 1988) के बाद भारत में इस आंदोलन को कुचल दिया गया था, लेकिन यह सिख आबादी के वर्गों, विशेष रूप से कनाडा जैसे देशों में सिख प्रवासी लोगों के बीच सहानुभूति और समर्थन पैदा करना जारी रखता है।

मुख्य शब्द

भारत कनाडा परिदृश्य, प्रवासी मुद्दा, खालिस्तान आंदोलन.

भारत और कनाडा सम्बन्ध

भारत ने 1947 में कनाडा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये। भारत और कनाडा के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, दो समाजों की बहु सांस्कृतिक, बहु जातीय और बहु-धार्मिक प्रकृति और लोगों के बहु- बीच मजबूत संपर्कों पर आधारित दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध हैं (पॉल आर मगोशी और शिवा एस हली)।

राजनीतिक

- भारत और कनाडा संसदीय संरचना और प्रक्रियाओं में समानताएं साझा करते हैं।
- भारत में, कनाडा का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा किया जाता है।
- कनाडा के बैंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में महाबाणिज्य दूतावास हैं, साथ ही अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में व्यापार कार्यालय भी हैं।

व्यापार

- भारत-कनाडा के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2022 में लगभग 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2021 की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- सेवा क्षेत्र को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में जोर दिया गया, 2022 में द्विपक्षीय सेवा व्यापार का मूल्य लगभग 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- कनाडाई पेंशन फंड ने संचयी रूप से भारत में लगभग 55 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है और तेजी से भारत को निवेश के लिए एक अनुकूल गतव्य के रूप में देख रहे हैं।
- 600 से अधिक कनाडाई कंपनियों की भारत में उपस्थिति है और 1,000 से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं।
- कनाडा में भारतीय कंपनियाँ सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, इस्पात, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिंग क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
- भारत-कनाडा मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत चल रही है।
- भारत और कनाडा के बीच 2023 में अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट (ईपीटीए) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
- यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, उत्पत्ति के नियमों, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार में तकनीकी बाधाओं और विवाद निपटान सहित कई क्षेत्रों को कवर करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) ने परमाणु सुरक्षा और नियामक मुद्दों में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए 16 सितंबर, 2015 को कनाडाई परमाणु सुरक्षा आयोग (सीएनएससी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भारत-कनाडाई एस एंड टी सहयोग मुख्य रूप से औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जिसमें नए आईपी, प्रक्रियाओं, प्रोटोटाइप या उत्पादों के विकास के माध्यम से आवेदन की संभावना है।
- नवंबर 2017 में नई दिल्ली में आयोजित प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में कनाडा एक भागीदार देश था।
- पृथ्वी विज्ञान विभाग और धर्वीय कनाडा ने शीत जलबायु (आर्कटिक) अध्ययन पर ज्ञान के आदान- प्रदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।
- 'मिशन इनोवेशन' कार्यक्रम के तहत, भारत सतत जैव ईंधन (IC4) के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों में कनाडा के साथ सहयोग कर रहा है।
- इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स ने कनाडा से कई नैनो उपग्रह लॉन्च किए हैं।

- इसरो ने 12 जनवरी, 2018 को लॉच किए गए अपने 100 वें सैटेलाइट PSLV में, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से कनाडाई पहला स्मृति उपग्रह भी उड़ाया।

शिक्षा और सांस्कृतिक

- शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट (एसआईसीआई) 1968 से भारत और कनाडा के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अद्वितीय द्वि-राष्ट्रीय संगठन है।
- नवंबर 2017 में गोवा में आयोजित 48 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कनाडा फोकस का देश था।
- कनाडा पोस्ट और इंडिया पोस्ट ने 2017 में दिवाली पर एक स्मारक टिकट जारी करने के लिए हाथ मिलाया।
- कनाडा पोस्ट ने 2020 और 2021 में फिर से दिवाली टिकट जारी किए।
- अक्टूबर 2020 में, कनाडा ने प्राचीन अन्नपूर्णा प्रतिमा के स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन की घोषणा की, जिसे एक कनाडाई कलेक्टर द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहित किया गया था और रेजिना विश्वविद्यालय में रखा गया था, तब से यह मूर्ति भारत को सौंप दी गई है और नवंबर 2021 में इसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर रखा गया है।

भारत—कनाडा संबंधों में विद्यमान चुनौतियाँ

सांस्कृतिक संवेदनशीलताएँ

भारत सरकार में कनाडा के भीतर कुछ सीमांत समूहों की उपस्थिति एवं गतिविधियों पर लगातार चिंताएँ प्रकट की हैं जो भारत में एक स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के विचार के प्रति सहानुभूति रखते हैं।

हाल ही में कनाडा ने एक ऐसे परेड की अनुमति दी जिसमें वर्ष 1984 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा नृशंस हत्या को प्रदर्शित किया गया था। इस निरूपण को सिख अलगाववादियों द्वारा हिंसा के महिमामंडन के रूप में देखा गया।

विल्सन सेंटर थिंकटैक में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन (डपर्टमेंट ऑफ इंडिया) का मानना है कि कनाडा में बढ़ती सिख गतिविधियों, ओटावा पर नई दिल्ली के बढ़ते दबाव और भारतीय चिंताओं को दूर करने के प्रति ओटावा की अनिच्छा के संयोजन में वर्तमान समय में द्विपक्षीय संबंधों को एक गहरे संकट की ओर धकेल दिया है।

वीज़ा और अप्रवासन नीतियाँ

हाल के वर्षों में ऐसी खबरें आई हैं कि भारतीय छात्रों को कनाडा में अध्ययन करने के लिये वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत में असंतोष पैदा हुआ है और चिंताएं बढ़ी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रों पर भिन्न रुख

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, यह संलग्न औपचारिक मुलाकात तक ही सीमित रही।

कृषि व्यापार विवाद

भारतीय डेयरी और पोल्ट्री उत्पादक दालों एवं कैनोला तेल जैसे विभिन्न उत्पादों के कनाडाई निर्यात पर व्यापार संबंधी चिंताएँ रखते हैं (बाल गोसाल)।

खालिस्तान आंदोलन की समरेखा क्या है?

- भारत की स्वतंत्रता और विभाजन
- इस आंदोलन की उत्पत्ति भारत की स्वतंत्रता और उसके बाद धार्मिक आधार पर विभाजन से मानी जाती है।

- पंजाब प्रांत जो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित था, ने कुछ सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसाये देखी और लाखों शरणार्थियों को जन्म दिया।
- महाराजा रणजीत सिंह के महान सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर पाकिस्तान में चली गई, साथ ही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जन्मस्थली ननकाना साहिब सहित पवित्र सिख रथल भी पाकिस्तान में चले गए।

2. स्वायत्त पंजाबी सूबे की मांग

- अधिक स्वायत्तता के लिए राजनीतिक संघर्ष आज़ादी के समय पंजाबी भाषी राज्य के निर्माण के लिए पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ शुरू हुआ।
- 1966 में वर्षों के विरोध के बाद, पंजाबी सूबा की मांग को प्रतिबिंबित करने के लिए पंजाब को पुनर्गठित किया गया।
- पूर्ववर्ती पंजाब राज्य को हिंदी भाषी, हिंदू बहुल राज्यों हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और पंजाबी भाषी, सिख-बहुल पंजाब में विभाजित किया गया था।

3. आनंदपुर साहिब संकल्प

- 1973 में, नए सिख बहुल पंजाब में प्रमुख ताकत, अकाली दल ने मांगों की एक सूची जारी की जो अन्य चीजों के अलावा राजनीतिक मार्ग का मार्गदर्शन करेगी। आनंदपुर साहिब संकल्प ने पंजाब राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग की, उन क्षेत्रों की पहचान की जो इसका हिस्सा होंगे। एक अलग राज्य का और अपना आंतरिक संविधान बनाने का अधिकार मांगा।
- जबकि अकालियों ने खुद बार बार यह स्पष्ट किया कि वे भारत से अलग होने की मांग नहीं कर रहे थे, भारतीय राज्य के लिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव गंभीर चिंता का विषय था।

4. भिंडरावाला

- जरनैल सिंह भिंडरावाले एक करिश्माई उपदेशक ने जल्द ही खुद को अकाली दल के नेतृत्व के विपरीत, 'सिखों की प्रामाणिक आबाज़' के रूप में स्थापित किया।
- ऐसा माना जाता है कि भिंडरावाले को संजय गांधी ने कांग्रेस के राजनीतिक लाभ के लिए अकालियों के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाया था। हालाँकि, 1980 के दशक तक भिंडरावाले इतना बड़ा हो गया कि वह सरकार के लिए समस्या बनने लगा।

5. धर्म युद्ध मोर्चा

- 1982 में भिंडरावाले ने अकाली दल के नेतृत्व के समर्थन से, धर्म युद्ध मोर्चा नामक एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने प्रदर्शनों और पुलिस के साथ झड़पों का निर्देशन करते हुए, स्वर्ण मंदिर के अंदर निवास किया।
- यह आंदोलन आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में पहली बार व्यक्त की गई मांगों के अनुरूप था, जिसमें राज्य की ग्रामीण सिख आबादी की चिंताओं को संबोधित किया गया था। हालाँकि, बढ़ते धार्मिक ध्वनीकरण, सांप्रदायिक हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ भिंडरावाले की अपनी कठोर बयानबाजी के बीच, इंदिरा गांधी की सरकार ने इस आंदोलन को अलगाव के समान घोषित कर दिया।

6. ऑपरेशन ब्लू स्टार

- ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 को शुरू हुआ, लेकिन भिंडरावाले और उसके भारी हथियारों से लैस समर्थकों के उम्र प्रतिरोध के कारण, टैकों और हवाई समर्थन के उपयोग के साथ सेना का ऑपरेशन मूल उद्देश्य से अधिक बड़ा और हिंसक हो गया।

- भिंडरावाले को मार दिया गया और स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त करा लिया गया. हालांकि इसने दुनिया भर के सिख समुदाय को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
- इसने खालिस्तान की मांग को भी हवा दी।

7. ऑपरेशन ब्लूस्टार के परिणाम

- अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई, जिससे विभाजन के बाद सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जहां बड़े पैमाने पर सिख विरोधी हिंसा में 8,000 से अधिक सिखों का नरसंहार किया गया।
- एक साल बाद, कनाडा स्थित सिख राष्ट्रवादियों ने एयर इंडिया की एक उड़ान को उड़ा दिया जिसमें 329 लोग मारे गए। उन्होंने दावा किया कि यह हमला भिंडरावाले की हत्या का बदला लेने के लिए था।
- पंजाब में सबसे भयानक हिंसा देखी गई और यह लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह का केंद्र बन गया जो 1995 तक चला।
- आबादी का बड़ा हिस्सा उग्रवादियों के खिलाफ हो गया और भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर अग्रसर हो गया।

खालिस्तान आंदोलन की आज क्या स्थिति है?

- पंजाब लंबे समय से शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन यह आंदोलन विदेशों में कुछ सिख समुदायों के बीच रहता है।
- प्रवासी भारतीयों में मुख्यतः वे लोग शामिल हैं जो भारत में नहीं रहना चाहते।
- इन लोगों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो 1980 के दशक के बुरे पुराने दिनों को याद करते हैं और इसलिए वहा खालिस्तान के लिए समर्थन मजबूत बना हुआ है।
- ऑपरेशन ब्लू स्टार और स्वर्ण मंदिर के अपमान को लेकर गहरा गुस्सा सिखों की नई पीढ़ियों में भी व्याप्त है। हालांकि, भले ही कई लोग भिंडरावाले को शहीद के रूप में देखते हैं और 1980 के दशक को काले समय के रूप में याद करते हैं, लेकिन यह खालिस्तान मुद्दे के लिए ठोस राजनीतिक समर्थन में प्रकट नहीं हुआ है।
- एक छोटा सा अल्पसंख्यक है जो अतीत से चिपका हुआ है, और वह छोटा अल्पसंख्यक लोकप्रिय समर्थन के कारण महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे बाएं और दाएं दोनों तरफ से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं (वर्मा जे एस)।

भारत—कनाडा का रिश्ता दूरने के खतरे में है।

कनाडा भारत राजनीतिक संबंधों की वर्तमान स्थिति ने अनिश्चितता का पहाड़ खड़ा कर दिया है। सवाल ये हैं: कैसी अनिश्चितता और किसके लिए? भारत कनाडा में आने वाले अप्रवासियों का एक प्रमुख मूल देश है, जो वहां स्वाभाविक नागरिक के रूप में बस गए हैं (ज्यादातर के पास भारत की विदेशी नागरिकता, आजीवन भारतीय वीजा या अर्ध-दोहरी नागरिकता है) और साथ ही स्थायी निवासी (पीआरएस) भी हैं। निवेशकों, उद्योगपतियों और व्यवसायियों से लेकर उच्च कुशल 'ज्ञान पेशेवर' से लेकर निम्न और मध्यम—कुशल 'सेवा कर्मचारी' तक। बसे हुए भारतीय प्रवासियों के अलावा, 'अस्थायी आगंतुक' भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र, प्रशिक्षु, विनियम विद्वान, पर्यटक और उनके परिवार हैं (जतिंदर मान)। इस प्रकार, उनमें से अधिकांश विदेशों में भारत की मानव पूँजी का एक बड़ा हिस्सा शामिल करते हैं, उनमें से कुछ को बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन के रूप में देश को बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।

कनाडा की जनगणना 2021 के अनुसार, देश में भारतीय मूल के 1.86 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, यानी, देश की 36.99 मिलियन आबादी का लगभग 5 प्रतिशत, और 32 मिलियन मजबूत वैश्विक भारतीय प्रवासी का 5.8 प्रतिशत। आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी) के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय

छात्रों के लिए 225,940 या 549,260 कुल अध्ययन परमिट में से 40: से अधिक भारतीयों को जारी किए गए थे। ये सभी प्रवासी और संभावित लोग कनाडा के साथ चल रहे राजनयिक विवाद से कैसे प्रभावित हैं और भारत समयबद्ध कांसुलर और वीज़ा सेवाओं में भारी कटौती कर रहा है?

प्रवासन पर वैशिक समझौता

कनाडा और भारत न केवल राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, बल्कि सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैशिक समझौते के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं, जिसे एक सम्मेलन में अपनाया गया था।

दिसंबर 2018 में मराकेश, मोरक्को में प्रवासन पर अंतर-सरकारी सम्मेलन। वैशिक विकास एजेंडे में प्रवासन को शामिल करने के लिए नागरिक समाज द्वारा तीन साल की लंबी बातचीत का परिणाम (अन्यथा प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र द्वारा बारीकी से संरक्षित और ध्वजांकित विशेष संप्रभुता की प्रचारित धारणा से प्रेरित) सदस्य राज्य), यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की एक ऐतिहासिक अगली कड़ी है।

भारत में धन प्रेषण मुख्य रूप से पश्चिम एशिया/खाड़ी देशों के प्रवासी श्रमिकों से होता है। कनाडा जैसे विकसित देशों में पीआर और प्रवासी सदस्य दोनों देशों में निवेश के स्रोत हैं। 2022 में, भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार भागीदार (13.7 बिलियन डॉलर से अधिक) था। 5.3 बिलियन डॉलर तक निर्यात के साथ कनाडा भारत का नौवां सबसे बड़ा भागीदार था। इसी तरह, भारत से आने वाले पर्यटक कनाडा के चौथे सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा बाजार में शामिल थे। इनमें से कई व्यापारी और निवेशक कनाडा में भारतीय प्रवासी के सदस्य हैं। 2021 में, भारत आने वाले कनाडाई लोगों ने 93 मिलियन डॉलर खर्च किए, और भारत से 89,500 से अधिक पर्यटकों ने कनाडा में 3.4 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो किसी भी एक देश से सबसे अधिक है। 2022 में, कनाडा और भारत द्विपक्षीय उड़ानों की संख्या पर प्रतिबंध हटाने पर सहमत हुए, जो पहले प्रति सप्ताह 35 तक सीमित थी। अब, व्यावहारिक रूप से दोनों तरफ से वीज़ा जारी करने पर रोक और/या प्रतिबंध के साथ यात्रा प्रतिबंध है, जिससे सीओवीआईडी –19 महामारी के दौरान वीज़ा आवेदनों और यात्रा योजनाओं में ढेर सारी यादें ताज़ा हो गई हैं, जिससे प्रवासियों और प्रवासी भारतीयों को एक बार अनिश्चितता के दुखों का सामना करना पड़ा। दोबारा (द हिंदू लेख 25 अक्टूबर 2023)।

इतिहास और एक माफ़ी

कनाडा में भारतीय प्रवासियों की संख्या 7,70,000 है लोग सिख धर्म से हैं। भारतीय मूल के सिख भारतीय प्रवासियों के कनाडाई टेपेस्ट्री पर हावी हैं, जो एक सदी से भी अधिक समय से अन्य धर्मों, मुख्य रूप से भारतीय हिंदुओं के साथ सौहार्दपूर्वक सह-अस्तित्व में हैं। कनाडा में अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन को कुछ समर्थन मिलने के कारण समय-समय पर पैदा हुए तनाव के बावजूद, भारतीय प्रवासी और कनाडाई समाज के बीच मजबूत संबंध बचे हुए हैं। किसी को इतिहास में 23 मई, 1914 की दुखद घटना पर वापस जाने की जरूरत है, जब 376 भारतीय यात्रियों के साथ वैकूवर आ रहे स्टीमशिप एसएस कोमागाटा मार्ल को औपनिवेशिक ब्रिटिश कानूनों के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था (सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट, 2015)। कनाडा. यात्री मुख्य रूप से पंजाब के सिख थे, लेकिन हिंदू मुसलमान और ईसाई भी थे, सभी कनाडा में एक नए जीवन की उमीद कर रहे थे। एक सदी बाद, कनाडाई सरकार ने कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम में निहित बहुसांस्कृतिक मूल्यों को कायम रखते हुए रचनात्मक भूमिका निभाई। 1 मई 2014 को, कनाडा पोस्ट द्वारा एसएस कोमागाटा मार्ल के आगमन की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया था, और 18 मई 2016 को, कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माफ़ी का एक औपचारिक बयान दिया। कोमा मार्ल घटना के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कनाडा की समृद्ध विविधता देश के लिए ताकत का स्रोत है। उन्होंने कहा, 'कोमागाटा मार्ल घटना कनाडा के अतीत पर एक दाग है। लेकिन हमारे देश का इतिहास ऐसा है जिसमें हम लगातार खुद को और एक-दूसरे को चुनौती देते हैं।' कनाडाई कौन है इसकी हमारी व्यक्तिगत परिभाषाओं का विस्तार करने के लिए। हमने अपने अतीत की गलतियों से सीखा है और सीखते रहेंगे, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन्हें कभी न दोहराएँ।

लोगों के संबंधों पर प्रभाव

अचानक, वह सब बंधन पर पड़ने लगता है टूटने की कगार पर. दुर्भाग्य से, दोनों सरकारों के बीच मौजूदा कूटनीतिक तनाव सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट के उद्देश्य 19 को कमजोर कर रहा है और इसने कनाडा और भारत में अपनी स्थिति के बारे में अनिश्चितता के संदर्भ में प्रवासियों और प्रवासी भारतीयों पर पर्दा डाल दिया है। यदि समस्या को जल्द ही हल नहीं किया गया, तो संबंधों में तनाव, विश्वास, समय और वफादारी के पोषित मूल्यों को अपूरणीय रूप से नष्ट कर देगा, जिससे सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट और विश्व स्तर पर एसडीजी को नुकसान होगा। तर्कसंगत सामूहिक विकल्प में हमारे पहले कक्षा के पाठों ने हमें सिखाया था कि इच्छा पहले आती है, और फिर किसी इच्छा या उद्देश्यपूर्ण कार्य को वास्तविकता में बदलने की क्षमता पैदा की जानी चाहिए।

अजीब बात है कि भारत और कनाडा के बीच विवाद में दोनों देशों की क्षमताएं पहले से ही मौजूद हैं लेकिन इच्छाशक्ति कम होती दिख रही है। दोनों सरकारों में इच्छा को बहाल करने के लिए चालक प्रत्येक पक्ष द्वारा विश्वास, समय और अपने प्रवासियों और डायरेस्पोरा और सबसे ऊपर अपने नागरिकों की वफादारी के तीन व्यक्तिगत मूल्यों को फिर से हासिल करने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता होगी।

आगे की राह

- **खालिस्तान के मुद्दे को हल करना:** सिख समुदाय के सदस्यों, भारत सरकार के प्रतिनिधियों और कनाडाई अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के बीच खुले एवं समावेशी संवाद को प्रोत्साहित किया जाए। दोनों देशों को किसी भी राजनीतिक अतिवाद से निपटने के लिये कानूनी कदम उठाने चाहिये।
- उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिये पारंपरिक क्षेत्रों से परे व्यापार का विस्तार सहयोग एवं आर्थिक विकास के लिये नए अवसरों के द्वारा खोल सकता है।
- **सांस्कृतिक विनियमन:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, कला प्रदर्शनियों और फिल्म समारोहों को प्रोत्साहन देने से एक-दूसरे की संस्कृतियों एवं परंपराओं की गहरी समझ को बढ़ावा मिल सकता है।
- **पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग:** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये साझा प्रतिबद्धता को देखते हुए भारत और कनाडा हरित प्रौद्योगिकियों, सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के क्षेत्र में मिलकर कार्य कर सकते हैं।
- **राजनयिक संलग्नता:** नियमित रूप से उच्च-स्तरीय राजनयिक संवाद और आदान-प्रदान वैशिक मुद्दों पर दोनों देशों के रुख को सरेखित करने तथा आपसी समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
- **सुरक्षा सहयोग:** आतंकवाद रोधी मुद्दों पर विशेष रूप से आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्यसमूह की रूपरेखा के माध्यम से प्रबल सहयोग स्थापित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत, कनाडा और खालिस्तान मुद्दे के बीच संबंध बहुआयामी हैं और ऐतिहासिक, राजनीतिक और प्रवासी कारकों से प्रभावित हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक संवेदनशील विषय बना हुआ है और समय के साथ विकसित होता रहता है। भारत और कनाडा दोनों को राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दों से आगे बढ़ते हुए सहयोग एवं सहकार्यता के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिये इस गतिशील साझेदारी के लिये भविष्य में बड़ी संभावनाएँ मौजूद हैं और दोनों देशों को इसके द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिये।

सन्दर्भ सूची

1. खालिस्तान, खोई हुई संप्रभुता पुनः प्राप्त करने का संघर्ष, एशियाई स्टडीज।
2. गुप्ता, शिव दयाल (1990), भारत कनाडा संबंध, जयपुर पब्लिशिंग हाउस।
3. हैदर, सुहासिनी (2023 सितंबर 27) जब भारत—कनाडा संबंध बहाल हुए, द हिन्दू /
4. केनी, केविन (2013) प्रवासी: एक बहुत संक्षिप्त परिचय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. बिनोद खदरिया (2023 अक्टूबर 25) भारत कनाडा का रिश्ता टूटने की कगार पर, द हिन्दू /
6. द कोमागाटा मारुः ए जर्नी टू कनाडा'' सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट, 2015।
7. सिंह शुभा, (2012) 'ट्रांसनेशनलिज़्म फ्रॉम बॉटम: इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा', टन वैन नैर्सन एट अल द्वारा संपादित वैश्विक प्रवासन और विकास में, प्रकाशक रुटलेज।
